नक्सलवादी समस्या के समाधान में सरकार की भूमिका

–डॉ. मुकेश कुमार

+2 शिक्षक, राजनीति विज्ञान

तिरहुत एकेडमी, मुजफ्फरपुर

सार संक्षेप :–नक्सलवाद देश की आंतरिक समस्या है। नक्सलवाद की उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान समय तक नक्सलवाद का रूप बदलता रहा है। नक्सलवाद की शुरुआती अवस्था में भूपति जमींदारों के विरुद्ध भूमिहीन कृषक मजदूर आमने–सामने थे। वहीं आज नक्सलवादी आंदोल सरकार एवं सुरक्षा बलों के बीच तक सीमित हो गई है। आंदोलन का स्वरूप चाहे जो भी हो उसके मूल में शोषित वर्गों का असहनीय शोषण और उत्पीड़न ही है। नक्सलवाद के उदय का प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक शोषण से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक छोटे कस्बे नक्सलवाड़ी से आरंभ नक्सली आंदोलन आज भारत के एक बड़े हिस्से में विकराल रूप ले चुका है। प्रतिवर्ष हजारों हत्याएँ हो रही है। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो रही है। जानमाल की अपूरणीय क्षति`स भारत की एकता एवं अखंडता पर कुठाराघात हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार का गठन देश के लिए गंभीर चुनौती है। नक्सलवादी आंदोलन उन्हीं क्षेत्रों में पनपा जहाँ शोषण एवं उत्पीड़न की घटनाएँ ज्यादा घटित हो रही है। वर्गीय विभेद के दलदल में फँसा भारपत की सामाजिक व्यवस्था ने शोषक एवं शोषितों के दो वर्ग पैदा कर दिए हैं। समय रहते नक्सलवाद पर काबू पाना आवश्यक है अन्यथा देश का हर जिला सुकमा का रूप धारण कर सकता है। इसलिए पूरी गंभीरता से नक्सलवाद के कारणों का अध्ययन कर नक्सलवादी समस्या का समाधान आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर इस दिश में प्रयास नहीं किए गए हैं, परन्तु अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं वह पर्याप्त नहीं है। नक्सलवाद देश की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की देन है। अतः इसका समाधान भी सामाजिक बराबरी एवं उन लोगों की आर्थिक उन्नति से संभव है जो सदियों से शोषित एवं पीड़ित है। सरकार के अनेक कदम सराहनीय भी है, फिर भी इस दिशा में और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द–विकास, नक्सलवाद, समस्या, समाधान, जाति, वर्ग, शोषण, सरकार

अध्ययन का उद्देश्य–प्रस्तुत अध्ययन में नक्सलवादी समस्या के समाधान में सरकार की भूमिका का अध्ययन किया जायेगा।

परिचय–स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्षों बाद भी भारत में आर्थिक विषमता की समाप्ति के आसार दिख नहीं रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकास के जिस प्रतिमान को अपनाया गया, उससे सामाजिक सोपान के निचले तबके पर विराजमान लोगों के बीच पहले से मौजूद असंतोष और भी ज्यादा बढ़ गया।

परिणामस्वरूप 1967 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के नक्सलवाड़ी में एक ऐसी घटना घटी जिसने बहुत जल्द ही विकराल रूप ले लिया। चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन उग्र से उग्रतर होता चला गया। शनैः–शनैः जमींदारों के विरुद्ध उत्पन्न यह आंदोलन आज सरकार एवं सुरक्षा बलों के बीच घमासान का केन्द्र बिन्दु बन गया है। वहीं सरकार का दावा ठीक इससे उलट है। सरकार नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अपील करती दिख रही है। समस्या की जड़ शोषण, गैर–बराबरी, उत्पीड़न, बेवसी, लाचारी, गरीबी और भूखमरी है। अतः अभी तक सरकारी स्तर पर किये गये प्रयास अंशतः सफल रहे हैं। अभी इस दिशा में और कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत आलेख में नक्सलवादी समस्या के समाधान में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन कर उचित सुझाव प्रस्तुत किया जायेगा।

नक्सली समस्या के समाधान में सरकार द्वारा किये गये प्रयास–

नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली समस्या से निपटने के लिए सरकार समय–समय पर काम करती रही है। हालांकि, इन इलाकों में किसी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना हमेशा ही एक चुनौती रही है। फिर भी सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं।

(1) इन्फ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सेलफोन कनेक्टिविटी, पुल, स्कूल जैसे विकास कार्यों पर काम किया जा रहा है।

(2) नक्सल प्रभावित इलाकों में अनगिनत मोबाईल टावर लगाये गये हैं ताकि संचार व्यवस्था दुरूस्त हो सके तथा इंटरनेट की मदद से ये नक्सली शिक्षा के महत्त्व को समझ कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। सरकार ने यातायात की सुविधा को ध्यान में रखकर हजारों किलोमीटर पक्की सड़क बना चुकी है ताकि वह बाकि दुनिया (भारत) के साथ संबंध स्थापित कर अपन विकास कर सके।

(3) सबसे अधिक नक्सल प्रभावित 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण कर उनका संचालन किया जा रहा है ताकि वे शिक्षा के बदौलत अपने अधिकार को पा सके, उनको समझ सके और राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा कर सके।

(4) जून 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नामक विशेष पहल की शुरुआत की गई है ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों के भटके लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन मार्च 2015 तक सिर्फ बिहार और झारखंड दो ही राज्यों को फंड आवंटित किया जा सका था।[1]

(5) वर्ष 2017 में नक्सल समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने आठ सूत्रीय 'समाधान' नाम से एक कार्ययोजना की शुरूआत की है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। समाधान से तात्पर्य है[2]–

S–Smart leadership (कुशल नेतृत्व)

A–Aggresive Strategy (आक्रामक रणनीति)

M–Motivation & Training (अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण)

A–Actionable Intelligence (अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था)

D–Dashboard based Key performance indicators and key result area (कार्ययोजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र)

H–Harnessing Technology (कारगर प्रौद्योगिकी)

A–Action Plan for each threat (प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना)

N–No access to financing (नक्सलियों के वित्त–पोषण को विफल करने की रणनीति)

नक्सली समस्या समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाये गए अन्य कदम–

सलवा जुडूम–सलवा जुडूम शब्द मूलतः आदिवासियों की एक बोली गोंडी से लिया गया है। सलवा का अर्थ शांति और जुडूम का अर्थ जुड़ना अर्थात् सलवा जुडूम का शाब्दिक शब्द 'शांति से जुड़ना' या 'शांति का कारवाँ' होता है। सलवा जुडूम की स्थापना 2005 में एक कांग्रेसी नेता महेन्द्र कर्मा ने की थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आदिवासियों के लिए घर वापसी का सरकारी अभियान है। यह नक्सलियों के विरोध में खड़ा हुआ आदिवासी समूह का आन्दोलन है। यह उसी जगह पैदा हुआ जहाँ नक्सलियों की जड़ें जमी हुई थी।

वास्तव में शुरू–शुरू में ये नक्सली या स्थानीय लोगों की भाषा में कहें तो दादा भाई आदिवासियों के सुख–दुख में सहभागी बने फिर धीरे–धीरे इनकी छोटी–छोटी समस्याओं, उनके आपसी विवाद, पटवारी एवं नाकेदार (वन रक्षक) की शिकायत से रूबरू होकर उनका निराकरण करने लगे। इससे इन आदिवासियों को लगने लगा कि इनके कारण ही हमें फायदा हो रहा है इसलिए ये शान्तिप्रिय आदिवासी इनका आदर करने लगे। इस तरह ये नक्सली उनके क्षेत्रों में जाकर इन वनवासियों का विश्वास जीतने में सफल रहे परन्तु, दूसरे चरण में ये नक्सली ग्रामीणों को ही निशाना बनाने लगे। जरा–जरा सी बात या पुलिस के मुखबिर होने के जरा से अन्देशे की बात पर गोली मार देना आम बात हो गई। इन्हें तेन्दूपत्ता के संग्रहण करने पर रोक लगा दी गई जिससे इन आदिवासियों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई। इन आदिवासियों का दादा भाईयों से विश्वास उठने लगा और अब वे मुक्ति की सोचने लगे और इसी मुक्ति की सोच का परिणाम था 'सलवा जुडूम'।

नक्सली समस्या के समाधान हेतु गृह मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम महत्त्वपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि इसकी वैधानिकता पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है तथापि यह अभियान आदिवासियों के हित में जारी है।[3]

ऑपरेशन ग्रीन हंट–नक्सली आंदोलन के खिलाफ गृह मंत्रालय द्वारा देशव्यापी, खासकर लाल गलियारे वाले राज्यों में नवम्बर 2009 में शुरू किया जानेवाला यह अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट कहलाया।

ऑपरेशन ग्रीन हंट का लक्ष्य–Clear, Hold & Clear है। इसके दो भाग हैं–पुलिस आधुनिकीकरण और तजी से सामाजिक, आर्थिक विकास पर बल। नक्सल प्रभावित जिलों में गरीबी, पिछड़ापन और यातायात की समस्या बहुत है। इनका तेजी से सामाजिक, आर्थिक विकास ऑपरेशन ग्रीन हंट का मुख्य उद्देश्य है।[4]

1998 में गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक 'कोआर्डिनेशन सेंटर' की स्थापना की गई। जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा डी.जी.पी. को शामिल किया गया। समन्वित तरीके से नक्सली चुनौती का हल निकालने के लिए नीतियाँ बनाने का जिम्मा सौंपा गया। गृहमंत्री अध्यक्ष एवं राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य बनाए गये। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के नोडल अधिकारी, इंटेलिजेंस, सी.आर.पी.एफ. एस.एस.बी. के अधिकारी होते हैं।

ऑपरेशन ग्रीन हंट के चलते नक्सली हिंसा में 40 फीसदी तक की कमी आई है।[5] दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में नक्सलवाद करीब–करीब खत्म हो चुका है।[6] पिछले 8710 वर्षों में बिहार में नक्सली हिंसा में काफी कमी आई है। इसका कारण है बिहार के विकास के कार्य को बखूबी अंजाम देना बिहार में विकास के कार्यों ने आशा की नयी किरण का संचार किया है उन तमाम लोगों के लिए जो भूखे अधनंगे व ताम सुविधाओं से महरूम जीवन यापन को अभिशप्त थे।

स्टीपेलचेस योजना–

यह अभियान वर्ष 1971 में चलाया गया। इस अभियान में भारतीय सेना तथा राज्य पुलिस ने भाग लिया था। इस अभियान के दौरान 20,000 नक्सली मारे गये थे।

आज बिहार में नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ रही है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार का विकास के कार्यों के प्रति गंभीर होना। अब सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरूस्त करने तथा गरीबों की आय बढ़ाने पर विशेष बल देना प्रारंभ कर दिया है, जिससे नक्सली गतिविधियों में स्पष्ट रूप से कमी आई है। बिहार में पिछले कई वर्षों से गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गई है जिनमें प्रमुख है जिस पर एक नजर डालना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

मनरेगा कार्यक्रम का सफल संचालन–

अधिनियम, 2005 (NREGA) देश के ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार के इच्छुक व्यस्क सदस्यों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्मिलित रूप से 100 दिनों का अकुशल/अर्द्धकुशल काम के लिए रोजगार सुनिश्चित करना।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- किसान क्रेडिट कार्ड
- जनवितरण प्रणाली
- बी0पी0एल0
- बिहार राशन कूपन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- स्वर्ण जयंतीी ग्राम स्वरोजगार योजना
- इंदिरा आवास योजना
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना

उपरोक्त सारी सरकारी योजनाओं द्वारा गरीबों, आदिवासियों, नक्सलियों की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की कोशिश जारी है ताकि भटके हुए युवा नक्सली नहीं बन सके तथा अपना और समाज का कल्याण हो सके।

निष्कर्ष :–

नक्सलवादी समस्या के लिए बहुत हद तक सरकारी उदासीनता को जिम्मेदार माना जाता है। यह समस्या देश की आंतरिक समस्या है और यहाँ की आवोहवा में ही पनपी है। अतः इसका समाधान भी यही होगा। बस जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति की। वोट की राजनीति से दूर नक्सली समस्याओं की तह में जाते हुए जिस दिन देश के कर्णधार यह ठान लेंगे कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है उसी दिन से नक्सलवादी आन्दोलन भारतीय इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा।

अतः हम कह सकते हैं कि बुद्ध और गांधी की भूमि पर हिंसा का कोई स्थान नहीं हैं आवश्यकता इस बात की है कि नक्सली भी अपनी हठधर्मिता छोड़े एवं सरकार वार्ता के लिए इनको तैयार कर मध्यम मार्ग अपनाते हुए इस समस्या का समाधान खोजे। बस आवश्यकता है दोनों ओर से दृढ़ शक्ति की। इस देश के प्रबुद्ध नागरिक का भी कर्तव्य है कि वे सकारात्मक पहल कर इस समस्या के समाधान की दिशा में सहयोग करें।

संदर्भ–सूची :–

1. www.dhyeyaias.com

2. www.drishtiias.com

3. गुहा रामचन्द्र, आदिवासीज, नक्सलाईट्स एंड इंडियन डेमोक्रेसी, आईएसबीएन–086232037

4. सेन मोहित, नक्सलाईट एण्ड नक्सलिज्म, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली' वार्षिक नं0 जनवरी 1971

5. परिवर्तन के सूत्र : पंचायत का साथ, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पृ.–50

6. विकास की योजनाएँ, बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट, पृ.–67

7. वही